**प्रेस विज्ञप्ति**

# वैश्विक स्तनपान नीति मूल्यांकन में भारत को उल्लेखनीय सफलता मिली

*स्तनपान में सफलता के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सहायता में अभी भी कमियों को दूर किया जाना बाकी है*

**नई दिल्ली। 1 अगस्त, 2025.** भारतीय स्तनपान संवर्धन नेटवर्क (BPNI) ने आज सुबह भारत की छठी World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) मूल्यांकन रिपोर्ट " Spotlight on Breastfeeding & Infant and Young Child Feeding in India." जारी की। यह छठी रिपोर्ट स्तनपान और शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार पर भारत की नीति और कार्यक्रम परिवेश का मूल्यांकन करती है।

भारत ने विश्व स्तनपान रुझान पहल (WBTi) पर अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, जो 100 के अधिकतम स्कोर में से 2018 के 45 स्कोर से बढ़कर 2025 में 62 हो गया है। देश की वैश्विक रैंकिंग 79वें से 41वें स्थान पर आ गई है, और यह पीले से नीले रंग के कोडिंग में ऊपर आ गया है, जो नीति और कार्यक्रम दोनों पर स्थिर प्रगति का संकेत देता है। यह स्तनपान और शिशु और छोटे बच्चों के आहार प्रथाओं की रक्षा, प्रचार और समर्थन करते हैं। हालांकि, यह शिशु आहार में गंभीर चुनौतियों की पृष्ठभूमि में होता है जैसा कि NFHS-5 डेटा द्वारा दर्शाया गया है जो दर्शाता है कि पहले घंटे में स्तनपान 41% है, केवल स्तनपान (0-6 month) -63% और पूरक आहार (after 6 month) 45% पर है और न्यूनतम स्वीकार्य आहार सिर्फ 11% है।

यह रिपोर्ट विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 के साथ आई है, जिसका विषय है: "स्तनपान को प्राथमिकता दें: स्थायी सहायता प्रणालियां बनाएं", और यह कार्रवाई के लिए गति प्रदान करती है।

छठी रिपोर्ट में कई उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि IMS Act और Maternity Benefits Act का प्रभावी कानूनी ढांचा, अस्पतालों में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय MAA programme, बेहतर सामुदायिक पहुंच, आपातकालीन एवं आपदा की स्थितियों तथा HIV जैसी परिस्थितियों में शिशु आहार को सुदृढ़ बनाना।"

हालाँकि, रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण कमियों को भी उजागर किया गया है, जिन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरणस्वरूप, समन्वय तंत्र की कमजोरियाँ, IMS Act के पालन में कमी, MAA programme के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, स्तनपान कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी (क्योंकि अधिकांश प्रसव निजी क्षेत्र में होते हैं), तथा अपर्याप्त वित्तीय सहायता। अन्य प्रमुख कमियाँ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभों की असमान उपलब्धता से जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को तकनीकी सहायता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आगे की कार्रवाई उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

आईवाईसीएफ प्रथाओं के 5 संकेतकों का मूल्यांकन करने में, रिपोर्ट ने NFHS-5 डेटा का उपयोग किया और संस्थागत जन्मों के प्रतिशत और जन्म के एक घंटे के भीतर प्रारंभिक स्तनपान दर के बीच एक बड़े अंतर को उजागर किया (चित्र 1)।

Indicator 2 मुख्य रूप से MAA programme से संबंधित है और यह दसों indicators में सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला है; यह एकमात्र Indicator है जिसे "लाल" श्रेणी में रखा गया है। भारत सरकार इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देकर प्रत्येक प्रांत और  जिले के लिए प्रशिक्षण, निगरानी और रिपोर्टिंग हेतु वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।

गत वित्तीय वर्ष के दौरान MAA कार्यक्रम ने लगभग 50 करोड़ रुपये के आवंटन के बावजूद केवल लगभग 33 करोड़ रुपये ही खर्च किए। केंद्र सरकार अपनी मौजूदा उपलब्धियों के आधार पर इस कार्यक्रम की पहुँच और गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है — इसके लिए अस्पतालों के स्टाफ को उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, तकनीकी सहायता देना और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत सरकार की एक और रणनीतिक पहल हो सकती है, जिसके माध्यम से अस्पतालों में सेवाओं की बेहतर पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है तथा प्रसव के बाद परामर्श (follow-up counselling) को भी सुदृढ़ किया जा सकता है।

"भारत की प्रगति सराहनीय और उत्साहवर्धक है। यदि भारत शीर्ष 10 देशों की रैंकिंग में स्थान प्राप्त करना चाहता है, तो बेहतर समन्वय, पर्याप्त वित्तीय समर्थन और IMS Act का प्रभावी पालन अत्यंत आवश्यक होगा," ऐसा कहना है डॉ. अरुण गुप्ता का, जो रिपोर्ट के मुख्य लेखक और BPNI (Breastfeeding Promotion Network of India) के संस्थापक हैं। महिलाओं और बच्चों को व्यावसायिक प्रभाव से बचाना स्तनपान में सफलता की कुंजी है।

रिपोर्ट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की गई है, ताकि राष्ट्रीय स्तनपान एवं शिशु एवं बाल्यावस्था पोषण (IYCF) संचालन समिति को पुनर्जीवित किया जा सके और इसके साथ ही बजटीय समर्थन के साथ एक चार वर्षीय राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई जा सके।

बीपीएनआई की नई केंद्रीय समन्वयक डॉ. नूपुर बिडला ने कहा, "अगर राष्ट्रीय संचालन समिति को पुनर्जीवित किया जाए और एक कार्य योजना विकसित और निगरानी की जा सके, तो इससे बड़ी सफलता मिल सकती है।" योजना में आपात स्थितियों सहित सभी क्षेत्रों में कार्रवाई शामिल होनी चाहिए।

पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी की सामुदायिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वंदना प्रसाद ने कहा, "हमें एक समन्वित, सुवित्तपोषित क्षमता निर्माण और सहायता योजना की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत हो। इसके बिना, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और माताओं को उन अस्पतालों में, जहाँ वे प्रसव कराती हैं और अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान, सहायता नहीं मिल पाती।" उन्होंने आगे तर्क दिया कि मातृत्व लाभ अधिनियम में तत्काल संशोधन की आवश्यकता है ताकि मातृत्व सुरक्षा कानूनों का दायरा सभी अनौपचारिक श्रमिकों तक बढ़ाया जा सके।

रिपोर्ट में कार्रवाई के लिए जिम्मेदार प्रत्येक मंत्रालय को विशिष्ट सिफारिशें की गई हैं। BPNI के साथ कई संस्थाओं ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है (Annex)

पूरी रिपोर्ट: लिंक https://bit.ly/46vQrBV

संपर्क:
डॉ. नूपुर बिडला पीएचडी Email Id- nupur@bpni.org Phone Number -9958163610
डॉ. अरुण गुप्ता Email Id-arun.ibfan@gmail.com Phone Number -98996 76306

**Annex- Core Group Members or Representatives of the following Organizations**

Doctors For You (DFY), Public Health Resource Network (PHRS), Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI), UNICEF India, National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW), Pediatric and Adolescent Nutrition (PAN) Society, National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) or Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development (SPNIWCD), Kalawati Saran Children's Hospital (KSCH)

**Fig. 1**

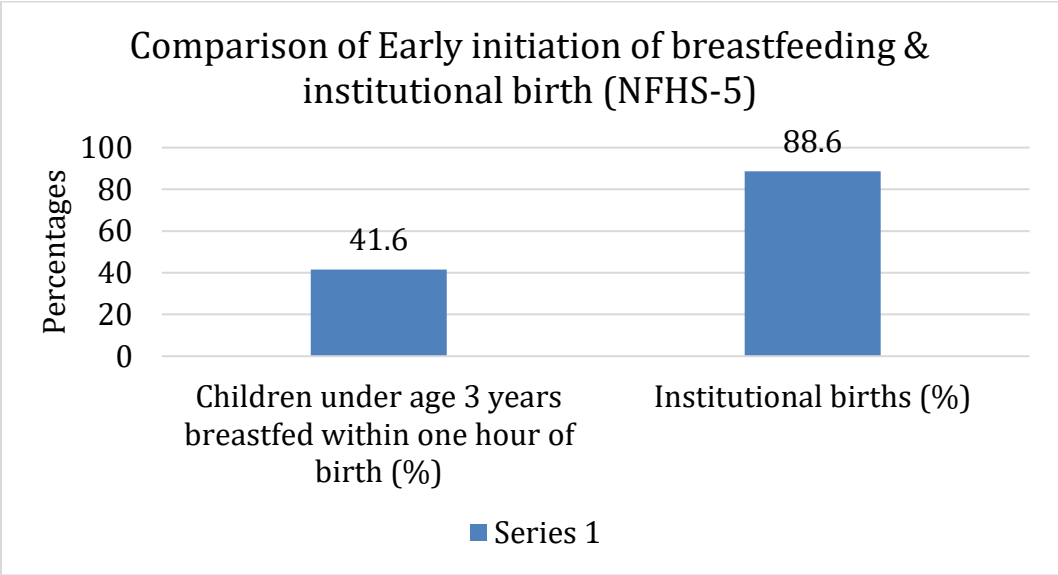


About WBTi

The World Breastfeeding Trends Initiative( WBTi) https://www.worldbreastfeedingtrends.org/ is a global assessment tool developed by BPNI/IBFAN and used in over 100 countries. Based on WHO's tools, it objectively evaluates ten indicators of policy and programmes and five of infant feeding practices, producing a composite score, colour coding, and global ranking. In partnership with the Global Breastfeeding Collective led by UNICEF and WHO a WBTi project has been launched to mobilise 50 countries by 2027. The Collective uses WBTi data annually to update its Report Cards.

**About BPNI www.bpni.org**

BPNI is a 33-year-old independent non-profit organisation committed to advancing child health and nutrition in India through protection, promotion and support of breastfeeding, with its mission to conduct policy analysis and advocacy, capacity building, development of tools for implementing programmes, the BPNI strives to influence the development of sustainable, evidence-based strategies to improve infant feeding practices across the country.